भारत सरकार

परमाणु ऊर्जा विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1416

जिसका उत्तर दिनांक 04.07.2019 को दिया जाना है

परमाणु संयंत्र विस्तार कार्यक्रम

1416. श्रीमती विजिला सत्यानंत :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने परमाणु संयंत्र विस्तार कार्यक्रम के लिए दस वर्ष के लिए प्रत्येक वर्ष लगभग 10,000 करोड़ का एक अनन्य बजट निर्धारित किया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के साथ संयुक्त उद्यम ने परमाणु ऊर्जा को वित्तीय बाधाओं से उभरने में मदद की है;

(ग) क्या विभाग अपने परमाणु संयंत्र विस्तार कार्यक्रम में वित्तीय बाधाओं का सामना कर रही थी; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन तथा प्रधान मंत्री कार्यालय (डॉ. जितेन्द्र सिंह) :

(क) लोक सभा के वर्ष 2016-17 बजट सत्र के दौरान दिनांक 29.2.2016 को वित्त मंत्री के बजट भाषण में नाभिकीय ऊर्जा के संबंध में निम्नलिखित संदर्भ शामिल था :

"विद्युत क्षेत्र में, दीर्घकालीन स्थायित्व के लिए हमें विद्युत उत्पादन के स्रोतों में विविधता लाने की आवश्यकता है । सरकार, नाभिकीय विद्युत उत्पादन में निवेश बढ़ाने के लिए अगले 15 से 20 वर्षों की अवधि हेतु व्यापक योजना बना रही है । इस प्रयोजन के लिए निवेश की आवश्यकता को पूरा करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के निवेशों के साथ-साथ प्रतिवर्ष रुपए 3,000 करोड़ तक का बजटीय आबंटन उपलब्ध कराया जाएगा ।"

(ख) योजनाबद्ध नाभिकीय ऊर्जा विस्तार कार्यक्रम के क्रियान्वयन में निहित बृहत् इक्विटी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनपीसीआईएल) का अन्य पीएसयू के साथ संयुक्त उद्यम (जेवी) बनाए जाने पर विचार किया गया था । इस संदर्भ में एनपीसीआईएल ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम - एनटीपीसी लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड और नेशनल एल्यूमीनियम कंपनी लिमिटेड (नाल्को) के साथ संयुक्त उद्यम (जेवी) बनाए । सरकार ने नाभिकीय विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने के लिए, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के साथ संयुक्त उद्यम बनाए जा सकने के लिए परमाणु ऊर्जा अधिनियम में भी संशोधन किया ।

(ग) तथा (घ) वर्तमान में निर्माणाधीन परियोजनाओं और ऐसी परियोजनाओं जिनके लिए प्रशासनिक अनुमोदन और वित्तीय संस्वीकृति प्राप्त है, की इक्विटी फंडिंग को मिला दिया गया है ।

*****